गया है। उक्त भूमि भारत कोकिंग कोल लि॰ के अधीन है। इस क्षेत्र में रहने वाले आवासियों को जीवन तथा संपत्ति की सुरक्षा को दृष्टिगत करते हुए तथा आवासों को खाली किए जाने की सूचना समय-समय पर दी जाती है। अब इस मामले पर स्थानीय जिला प्रशासन द्वारा भी त्वरिता से कार्रवाई की गई है।

Irregularities in allotment of coal mining blocks

3034. SHRI SATISH PRADHAN: Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) whether in allotment and operations of coal mining blocks to Ispat Group, serious irregularities have been committed and complaints received in this regard;

(b) if so, the details thereof;

(c) the details of the action taken in this regard; and

(d) the details of steps taken/proposed to be taken to safeguard the national interest in formulating detailed revised guidelines for mining operations in the wake of privatisation/ liberalisation?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRIMATI KANTI SINGH): (a) and (b) A captive mining block has been identified for allotment to Central India Coal Company in which Ispat Urja Ltd. is required to hold not less than 26% of the equity at all times. The promotors have proposed some changes in the equity structure of the companies which *prima facie* are not in accordance with the provisions rendering them eligible to mine coal. A concern has also been expressed that coal mining operations may pose a hazard for the operations in the Chandrapur Ordnance Factory which is in the vicinity.

(c) The Central Government has not so far conveyed its concurrence for issuance of a mining lease for coal to the Central India Coal Company as required under the MM(R&D) Act and the M.C. Rules.

M/s. Ispat Urja Ltd., M/s. Central India Coal Company Ltd. and M/s. Central India Power Company Ltd., the companies promoted by the Ispat Group in India have been issued show-cause notices on the structure of their companies.

(d) Coal mining is governed by the provisions of the MM(R&D) Act, 1957, Mineral Concession Rules, 1960 Coal Conservation & Development Act, 1974, Coal Conservation & Development Rules 1975 and the Coal Bearing Areas (Acquisition) Act etc. These Acts are equally applicable to the public sector as well as the private sector coal companies and regulate mining operations well with national interests in view. These Acts/ Rules continue to be inoperation even in the wake of the libersalisation in coal sector.

कोयला भंडारों का आकलन करने हेतु सर्वेक्षण

3035. **श्री शिव चरण सिंह:** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न राज्यों में कोयले के छिपे हुए भंडारों का आकलन करने हेतु कोई सर्वेक्षण किया है; और

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह): (क) और (ख) कोयले के लिए क्षेत्रीय तथा विस्तृत दोनों तरह का अन्वेषण विभिन्न केन्द्रीय सरकारी अभिकरणों अर्थात् भारतीय भू-सर्वेक्षण, कोल इंडिया लि॰ तथा खनिज अन्वेषण निगम लि॰ तथा असम, मेघालय तथा नागालैण्ड की राज्य सरकारों के अभिकरणों द्वारा किया जाता है ताकि उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कोयले के भण्डारों का मूल्यांकन किया जा सके।

1.1.1997 की स्थिति के अनुसार भारतीय भू-सर्वेक्षण द्वारा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए 889.81 मि॰ टन कोयले के भंडारों का मूल्यांकन किया गया है। इस संबंध में राज्य-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(मि॰ टन में)

राज्य	कोयले के भण्डार
असम	320.21
मेघालय	459.43
नागालैण्ड	19.94
अरुणाचल प्रदेश	90.23
जोड़	889.81